निजी कॉरपोरेट निवेश: 2024-25 में संवृद्धि और 2025-26 के लिए संभावना

स्निग्धा योगिन्द्रन, सुक्ति खांडेकर, राजेश बी कावेडिया और आलोक घोष द्वारा ^

यह आलेख बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर 2024-25 के दौरान भारत में निजी कॉरपोरेट निवेश के इरादों और 2025-26 के लिए संभावनाओं की जांच करता है। बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 2024-25 के लिए ₹3.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यह निजी कॉरपोरेट्स के निवेश के प्रति आशावाद को इंगित करता है। सभी चैनलों के माध्यम से वित्तपोषित पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर, पूंजीगत व्यय 2025-26 में बढ़कर ₹2.67 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है, जो मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे, बेहतर बैलेंस शीट, बढ़ती क्षमता उपयोग, सुगम चलनिधि स्थिति, अवसंरचना को प्रोत्साहन और फरवरी 2025 से शुरू होने वाली 100-बीपीएस नीति दर में कटौती से समर्थित है।

परिचय

निजी कॉरपोरेट निवेश भारत के दीर्घकालिक विकास पथ में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बना हुआ है। महामारी के वर्षों के दौरान सुस्त गतिविधियों के बाद, सहायक कारकों के संयोजन से निवेश चक्र में नई जान आ रही है। 2024-25 में, मजबूत जीडीपी वृद्धि, निरंतर अवस्फीति और परिणामस्वरूप अनुकूल मौद्रिक नीति रुख समष्टि आर्थिक पृष्ठभूमि की विशेषता रही। घरेलू अर्थव्यवस्था में 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ लचीलापन जारी रहेगा, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो मजबूत घरेलू माँग और सार्वजनिक अवसंरचना निवेश में निरंतर प्रगति से समर्थित है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय कॉरपोरेट जगत बैलेंस शीट सुधार के दौर से गुज़रा है, जिसे डीलीवरेजिंग, बेहतर नकदी प्रवाह और कई क्षेत्रों में मजबूत लाभप्रदता से बढ़ावा मिला है (आरबीआई, एफएसआर, जून 2025)। बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रचुर चलनिधि ने ऋण परिवेश को और बेहतर बनाया है, जिससे क्षमता विस्तार के लिए वित्तपोषण तक आसान पहुँच संभव हुई है। उच्च-आवृत्ति संकेतकों में हालिया रुझान—जैसे पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ता आयात, बेहतर क्षमता उपयोग और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजारों में बढ़ता प्रवाह—विभिन्न कंपनियों में नए सिरे से निवेश की इच्छा का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ, जैसे उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ, ऊर्जा संक्रमण निवेश और डिजिटल अवसंरचना विस्तार, कॉर्पोरेट्स को नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

इस सुधार के बीच, इस आलेख का मुख्य उद्देश्य निजी कॉरपोरेट निवेश के उभरते परिदृश्य और उसकी निकट भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना है। इस विश्लेषण को कई प्रश्न निर्देशित करते हैं: क्या निवेश की मंशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? कौन से क्षेत्र और प्रदेश इस सुधार का नेतृत्व कर रहे हैं? पारंपरिक बैंक ऋण के अलावा वैकल्पिक वित्तपोषण माध्यमों की क्या भूमिका है?

चूँकि कॉरपोरेट बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने में समय लगता है, इसलिए कई देश कॉरपोरेट निवेश और संभावित योजना के निकट-अवधि के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण, निवेश की मात्रा और समय के बारे में प्रमुख जानकारी प्रदान करते हैं जिससे कंपनियों के निवेश इरादों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके, जिसकी निकट से मध्यम अवधि में साकार होने की उम्मीद है।

भारतीय संदर्भ में, रिज़र्व बैंक निवेश परिदृश्य का आकलन करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी के माध्यम से निजी पूंजीगत

^ लेखक सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग से हैं। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

व्यय योजनाओं पर नज़र रख रहा है। यह आलेख 2024-25 में निजी कंपनियों द्वारा शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की विशेषताओं, वित्त पोषण पैटर्न, क्षेत्रीय और स्थानीय वितरण, और चरणबद्ध रूपरेखा का विश्लेषण करता है। पाइपलाइन परियोजनाओं[1] से परिकल्पित पूंजीगत व्यय, जो कार्यान्वयन के लिए पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को संदर्भित करता है, का भी 2024-25 के लिए अनुमान लगाया गया है। यह आलेख निवेश इरादों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बैंक/एफआई प्रतिबंधों, बाहरी वाणिज्यिक उधार और इक्विटी निर्गम जैसे कई स्रोतों का उपयोग करता है। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के समय और संरचना पर केंद्रित होते हुए यह आलेख 2025-26 के लिए निवेश चक्र और इसके समष्टि आर्थिक निहितार्थों के बारे में मूल्यवान दूरदर्शी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यह आलेख पाँच खंडों में संरचित है। खंड II में कार्यप्रणाली और धारणाओं का विवरण दिया गया है। खंड III में 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की गई है, जिसमें वित्तपोषण पैटर्न और क्षेत्रीय/स्थानीय वितरण शामिल है। खंड IV में चरणबद्ध रूपरेखा का मूल्यांकन और निवेश वृद्धि के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और खंड V में अध्ययन का समापन किया गया है।

II. कार्यप्रणाली और धारणाएँ

निजी कॉरपोरेट निवेश के अल्प से मध्यम अवधि के परिदृश्य का आकलन करने के लिए, यह अध्ययन रंगराजन (1970)[2] द्वारा विकसित कार्यप्रणाली ढाँचे को अपनाता है। यह विश्लेषण तीन मुख्य डेटा स्रोतों पर आधारित है जो पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विविध वित्तपोषण मार्गों को दर्शाते हैं: (i) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ, (ii) पूंजीगत व्यय से संबंधित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), जिनमें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) और रुपया-मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) शामिल हैं, और (iii) पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), और अधिकार निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि।

पूँजी निवेश की दोहरी गणना और उसके परिणामस्वरूप अति-अनुमान से बचने हेतु, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक परियोजना को डेटासेट में केवल एक बार ही शामिल किया जाए। यह रिज़र्व बैंक के आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करके और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी को शामिल करके प्राप्त किया गया है, भले ही किसी परियोजना को कई स्रोतों से वित्त पोषित किया गया हो। यह अध्ययन विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर केंद्रित है जिन्हें उपर्युक्त स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है, जिनकी परियोजना लागत ₹10 करोड़ से अधिक है, और परियोजना में निजी कंपनियों की बहुलांश हिस्सेदारी है। केंद्र और/या राज्य सरकारों के पास बहुलांश हिस्सेदारी वाली परियोजनाएँ, और ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ इस अध्ययन के दायरे से बाहर हैं।

ये अनुमान इस धारणा के तहत निकाले गए हैं कि कंपनियाँ अपनी प्रत्याशित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान विभिन्न कारणों से वास्तविक निवेशों से भिन्न हो सकते हैं, जैसे (ए) नियोजित निवेशों के समय या पैमाने में संशोधन, (बी) वित्तपोषण के पैटर्न में बदलाव—उदाहरण के लिए, ऋण या इक्विटी वित्तपोषण को आंतरिक स्रोतों या एफडीआई से प्रतिस्थापित करना, जो आरबीआई द्वारा एकत्र किए गए परियोजना वित्त डेटा में शामिल नहीं हैं, और (सी) नई परियोजनाओं का उदय या पहले की परियोजनाओं का रद्द होना। इसके अलावा, यह जानने की आवश्यकता है कि आलेख में प्रस्तुत विश्लेषण केवल उन पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर आधारित है जिनके लिए निजी कंपनियों ने वित्तपोषण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया था और तदनुसार, ये अनुमान निवेश गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करते हैं और निजी कॉरपोरेट स्थिर पूंजी निर्माण के राष्ट्रीय लेखा-आधारित अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

---

[1] पाइपलाइन परियोजनाएँ वे परियोजनाएँ हैं जो पहले से ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा चुकी हैं। पाइपलाइन परियोजनाओं से पूंजीगत व्यय किसी वर्ष के लिए परिकल्पित राशि होती है, जिसे उस वर्ष से पहले स्वीकृत किया गया हो।

[2] यह कार्यप्रणाली 19 दिसंबर, 1970 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा लिखित आलेख "फॉरकास्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कॉर्पोरेट सैक्टर" में प्रकाशित हुई थी।

III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ

2024-25 के दौरान, लगभग 907 परियोजनाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिली, जिनकी कुल लागत ₹3,67,973 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष स्वीकृत 944 परियोजनाओं की कुल लागत ₹3,91,003 करोड़ थी (अनुलग्नक सारणी ए1)।

2024-25 के दौरान, 448 निजी कंपनियों, जिन्होंने पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तपोषण नहीं लिया था, ने पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी के माध्यम से ₹96,966 करोड़ जुटाए, जबकि 229 अन्य कंपनियों ने अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के तहत घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से ₹32,295 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2024-25 के दौरान 1,584 परियोजनाओं की निवेश योजना बनाई गई, जिसमें ₹4,97,235 करोड़ के निवेश की मंशा थी, जबकि 2023-24 में ₹5,47,734 करोड़ के निवेश की मंशा वाली 1500 परियोजनाएं बनाई गई (अनुलग्नक सारणी ए1 - ए4)।

i) आकार-वार

2024-25 के दौरान, दस मेगा परियोजनाएँ (परियोजना लागत ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक) और 75 बड़ी परियोजनाएँ (₹1000 करोड़-₹5000 करोड़), बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की गई, जिनकी कुल परियोजना लागत में क्रमशः 25.8 प्रतिशत और 37.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इन मेगा/बड़ी परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध योजनाओं से विचलन मध्यम अवधि में समग्र पूंजीगत व्यय पैटर्न को प्रभावित कर सकता है (अनुलग्नक सारणी ए5)।

ii) उद्देश्य-वार

2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत में ग्रीन फील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का हिस्सा सर्वाधिक लगभग 92 प्रतिशत रहा, जो पूर्व में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। ग्रीन फील्ड निवेश आम तौर पर कंपनियों के लिए नए और अतिरिक्त संसाधन और परिसंपत्तियाँ लाता है और सकल स्थिर पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में अधिक निवेश भविष्य में निजी कंपनियों द्वारा संभावित क्षमता विस्तार की ओर इशारा करता है। मौजूदा परियोजनाओं[3] के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश का कुल परियोजना लागत में 7.8 प्रतिशत हिस्सा रहा (अनुलग्नक सारणी ए6)।

iii) उद्योग-वार

2024-25 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण दर्शाता है कि अवसंरचना क्षेत्र[4] परियोजनाओं की

चार्ट 1: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समग्र लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

(प्रतिशत)

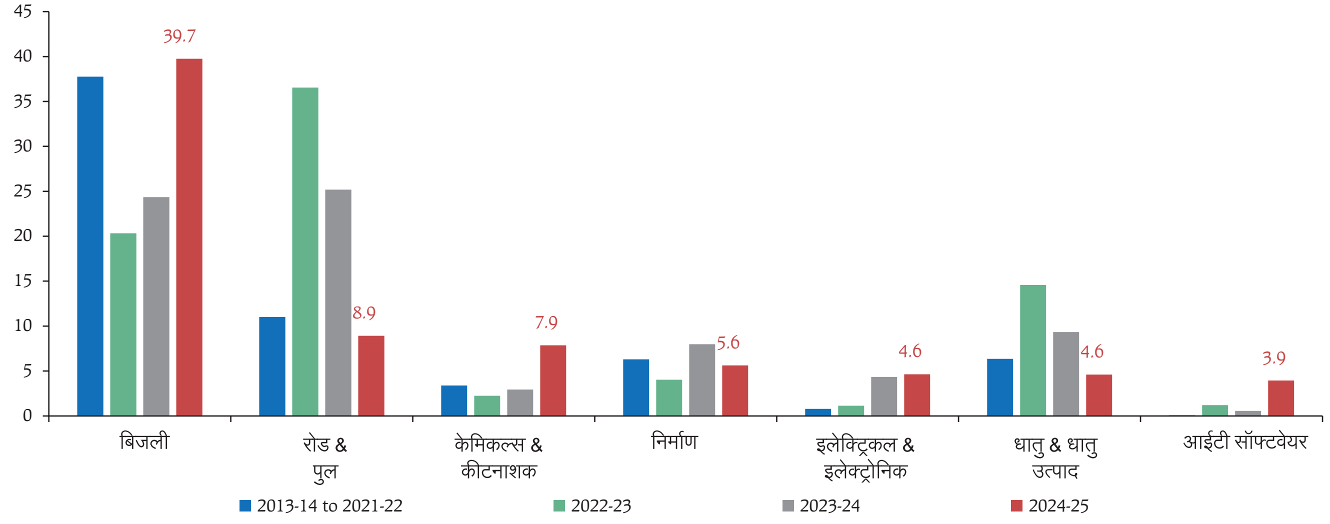

स्रोत: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना- वित्त डेटा; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

[3] मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश आम तौर पर उत्पादन और/या इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं के उन्नयन के लिए आवश्यक निवेश से संबंधित होता है।

कुल लागत में 50.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख क्षेत्र बना रहा, जो मुख्य रूप से 'बिजली' में निवेश से प्रेरित है, उसके बाद 'सड़क और पुल' (अनुलग्नक सारणी ए7) का स्थान है। हालाँकि, परियोजनाओं की कुल लागत में अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं की हिस्सेदारी पिछले दस वर्षों में सबसे कम थी। अवसंरचना के अलावा, अन्य प्रमुख उद्योगों में, रसायन और कीटनाशक, निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपकरण, और धातु और धातु उत्पादों का भी परियोजनाओं की कुल लागत में बड़ा हिस्सा है (चार्ट 1 और अनुलग्नक सारणी 7)।

iv) राज्य-वार

स्थानीय कारक, जैसे कच्चे माल की पहुँच, आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता, कुशल श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त अवसंरचना का होना, बाजार का आकार, विकास क्षमता और माँग की स्थितियाँ, निवेश के लिए गंतव्य चुनने में महत्वपूर्ण रहते हैं। विश्लेषण के उद्देश्य से, इस आलेख में, कई राज्यों में फैली परियोजनाओं को "बहु-राज्य" परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार वितरण से पता चला है कि शीर्ष पाँच राज्य, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 2024-25 के दौरान परियोजनाओं की कुल लागत में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सुधरी है (चार्ट 2 और अनुलग्नक सारणी ए8)।

IV. निवेश इरादों की चरणबद्ध रूपरेखा

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा, निजी निगमों के निकट-अवधि (एक वर्ष आगे) निवेश परिदृश्य को दर्शाती है। 2024-25 में स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध रूपरेखा यह दर्शाती है कि कुल प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का 39.3 प्रतिशत (₹1,44,782 करोड़) वर्ष 2024-25 के अंत तक निवेश करने की योजना थी, जबकि 35.2 प्रतिशत (₹1,29,591 करोड़) 2025-26 में और 25.4 प्रतिशत (₹93,600 करोड़) बाद की अवधि में खर्च करने की योजना है। 2024-25 तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा के आधार पर, परिकल्पित पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ ₹2,95,234 करोड़ दर्ज किया गया (अनुलग्नक सारणी ए1)।

निजी कंपनियों द्वारा ईसीबी और आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए संसाधन उनकी निवेश गतिविधियों के वित्तपोषण

चार्ट 2: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समग्र लागत में प्रमुख राज्यों का हिस्सा
(प्रतिशत)

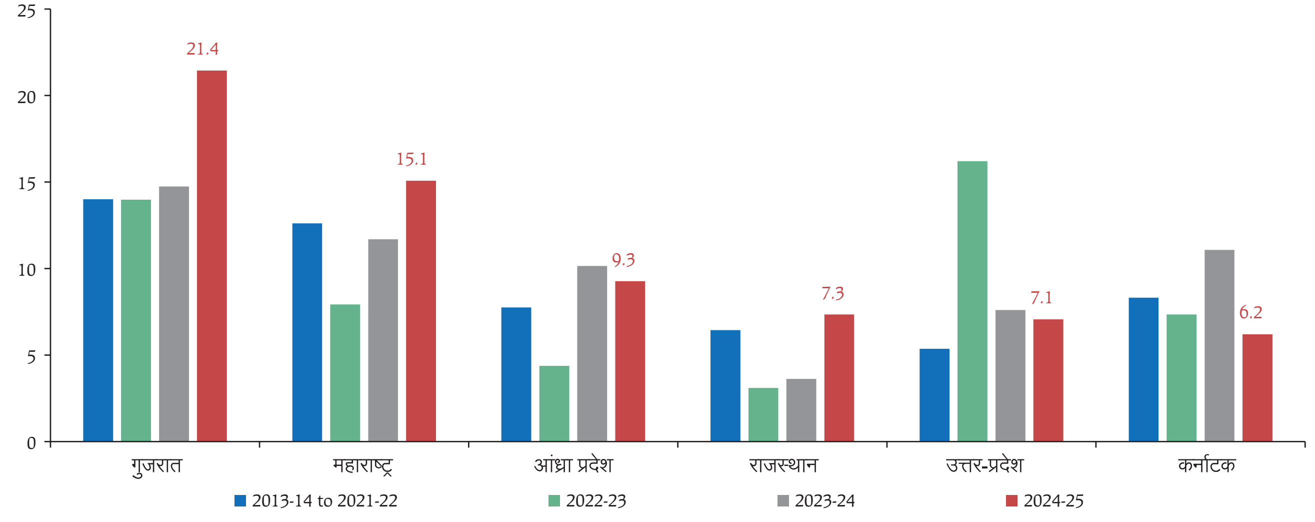

स्रोत: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना- वित्त डेटा; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

[4] अवसंरचना क्षेत्र में (ए) बिजली, (बी) दूरसंचार, (सी) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (दी) भंडारण और जल प्रबंधन, (ई) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी और आईटी पार्क, और (एफ) सड़कें और पुल शामिल हैं।

के पूरक हैं। 2024-25 और उससे पहले की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से, 2024-25 के दौरान किए जाने वाले नियोजित पूंजीगत व्यय ₹1,00,747 करोड़ के मजबूत स्तर पर बने रहे, हालाँकि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। साथ ही, पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से नियोजित पूंजीगत व्यय 2024-25 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹18,943 करोड़ हो गया, हालाँकि कुल परिकल्पित पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा नगण्य रहा (अनुलग्नक सारणी ए2 और ए3)।

कुल मिलाकर, वित्त पोषण के विभिन्न चैनलों के आधार पर, जैसा कि पहले बताया गया है, 2024-25 में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा कुल ₹4,14,923 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना था, जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजीगत व्यय के समान था। संदर्भ वर्ष से पहले के वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा दर्शाती है कि परिकल्पित पूंजी निवेश 2024-25 में ₹1,68,204 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1,91,073 करोड़ हो गया; जबकि वित्त पोषण के सभी चैनलों को मिलाकर, यह 2024-25 के ₹2,20,132 करोड़ की तुलना में 2025-26 में ₹2,67,432 करोड़ है (अनुलग्नक सारणी ए1 और ए4)।

V. निष्कर्ष

परियोजना वित्त डेटा का विश्लेषण निवेश के प्रति कम आशावाद की ओर इशारा करता है, जैसा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान परियोजनाओं की कुल लागत में कमी से परिलक्षित होता है। अवसंरचना क्षेत्र ने परिकल्पित पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित करना जारी रखा, जिसका नेतृत्व 'विद्युत' क्षेत्र कर रहा है। 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में से, 39.3 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक निवेश करने की योजना थी, 35.2 प्रतिशत 2025-26 के लिए प्रदान किया गया है और शेष 25.4 प्रतिशत बाद के वर्षों में निवेश करने की परिकल्पना की गई है। तीनों चैनलों के माध्यम से वित्तपोषित पाइपलाइन परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा बताती है कि परिकल्पित पूंजीगत व्यय 2024-25 के ₹2,20,132 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹2,67,432 करोड़ हो सकता है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय कंपनियाँ नए वित्तीय वर्ष में बेहतर बैलेंस शीट, ज़्यादा नकदी भंडार, बेहतर लाभप्रदता और विविध वित्तपोषण स्रोतों तक बेहतर पहुँच के साथ प्रवेश कर रही हैं। अवसंरचना के लिए निरंतर नीतिगत प्रोत्साहन, निरंतर अवस्फीति, कम ब्याज दरों, सुगम चलनिधि स्थितियों और बढ़ते क्षमता उपयोग के साथ, निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, निवेश परिदृश्य सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है। जहाँ भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और माँग में मंदी जैसे बाहरी जोखिम निवेश की भावना को प्रभावित कर सकते हैं, वहीं घरेलू बुनियादी ढाँचे मज़बूत दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश की संरचना—मुख्यतः ग्रीनफ़ील्ड अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा संचालित—न केवल चक्रीय सुधार, बल्कि संरचनात्मक क्षमता निर्माण का भी संकेत देती है। कंपनियों के इरादों को क्रियान्वयन में बदलने की क्षमता भारत के विकास के अगले चरण को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। इसलिए, परियोजना कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और सहायक नीतिगत उपाय इस गति को स्थायी आर्थिक लाभ में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

संदर्भ:

C Rangarajan (1970). Forecasting Capital Expenditure in the Corporate Sector. *Economic and Political Weekly (EPW)*, Volume No. 5, Issue No. 51, Page 2049-2051.

RBI (2025). Financial Stability Report, June. Retrieved from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/0FSRJUNE20253006258AE798B4484642AD861CC35BC2CB3D8E.PDF

सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

स्वीकृति वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़)	संशोधन/निरस्त करने के कारण परियोजना लागत^ (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2013-14 तक				1,70,603	93658	34172	14421	4722	1472								
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)	14,920	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036							
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)	3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220						
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)	1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086					
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)		620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242				
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)			569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,663	35			
2019-20	320	2,00,038	1,75,83 (12.1)					4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	14,114	2,299	194		
2020-21	220	75,558	75,558 (0.0)						2,491	3,709	29,013	26,166	9,711	3,867	601		
2021-22	401	1,43,314	1,42,111 (0.8)							3,610	10,543	59,622	44,306	18,447	3,541	1,646	396
2022-23	547	2,66,547	2,66,621 (0.0)							1,127	2,150	16,663	87,996	92,539	47,942	15,338	2,865
2023-24	944	3,90,978	3,91,003 (0.0)								2,235	6,783	39,455	1,63,608	1,15,926	44,499	18,497
2024-25	907	3,67,973										1,476	3,073	13,204	1,27,029	1,29,591	93,600
कुल योग &				**1,90,662**	**1,40,253**	**1,38,595**	**1,43,077**	**1,33,172**	**1,46,665**	**1,43,025**	**1,38,169**	**1,53,013**	**2,01,561**	**2,93,999**	**2,95,234**	**1,91,073**	**1,15,358**
प्रतिशत परिवर्तन					**-26.4**	**-1.2**	**3.2**	**-6.9**	**10.1**	**-2.5**	**-3.4**	**10.7**	**31.7**	**45.9**	**0.4**	**#**	

&: कॉलम का योग किसी विशेष वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह अनुमान पूर्व-निर्धारित है और इसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। ये वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेशों से भिन्न हैं।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में स्वीकृत होने वाले संभावित प्रस्ताव का पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।

^: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधन/निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का चरणबद्ध विकास*

स्वीकृति वर्ष ↓	जारी किए गए LRN की संख्या	कुल दिया गया ऋण (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			78,864	27,376	4,896											
2014-15	478	57,327		36,791	16,806	3,151	575	2	2							
2015-16	314	38,885			28,998	7,311	2,572	4								
2016-17	346	22,154				14,953	6,005	1,192	2	2						
2017-18	419	37,896					17,822	13,054	6,484	529	7					
2018-19	515	72,490						46,221	17,725	1,236	5,398	1,844	66			
2019-20	495	95,491							65,367	17,157	11,717	965	285			
2020-21	362	40,564								21,865	13,574	3,219	1,675	231		
2021-22	363	51,059								13	29,315	16,554	5,089	89		
2022-23	393	81,101										33,927	31,785	14,438	950	
2023-24	433	1,50,421											76,336	34,178	21,169	18,738
2024-25	448	96,966											12	51,811	40,660	4,483
कुल योग &			**78,864**	**64,167**	**50,700**	**25,415**	**26,974**	**60,473**	**89,580**	**40,802**	**60,011**	**56,509**	**1,15,248**	**1,00,747**	**62,779**	**23,221**
प्रतिशत परिवर्तन				**-18.6**	**-21.0**	**-49.9**	**6.1**	**124.2**	**48.1**	**-54.5**	**47.1**	**-5.8**	**103.9**	**-12.6**	**#**	

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता नहीं मिली।

**: रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में निकाले जाने वाले संभावित प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है। ये वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

LRN: ऋण पंजीकरण संख्या।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण*

के दौरान जारी की गई ↓	कंपनियों की संख्या	अनुमानित पूंजीगत व्यय (₹करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			494	492	70											
2014-15	24	1,078		189	557	332										
2015-16	40	4,511		11	644	2,753	849	183	71							
2016-17	29	1,159			14	471	368	163	143							
2017-18	51	1,538					419	327	787	5						
2018-19	39	609						506	90	13						
2019-20	12	53						2	49	2						
2020-21	12	663								139	421	84	19			
2021-22	27	3,410								10	757	1,304	939	400		
2022-23	42	3,629										1,172	2,181	276		
2023-24	123	6,310										58	2,999	2,316	937	
2024-25	229	32,295											199	15,951	12,643	3,503
कुल योग &			**494**	**692**	**1,285**	**3,556**	**1,636**	**1,181**	**1,140**	**169**	**1,178**	**2,618**	**6,337**	**18,943**	**13,580**	**3,503**
प्रतिशत परिवर्तन				**40.1**	**85.7**	**176.7**	**-54.0**	**-27.8**	**-3.5**	**-85.2**	**597.0**	**122.2**	**142.1**	**198.9**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता नहीं मिली।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में लागू होने वाले प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है

।&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी*/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

स्वीकृति का वर्ष ↓	कंपनियों या बैंकों/ एफआई/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी/ आईपीओ की संख्या	परयोजना लागत (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			2,49,961	1,21,526	39,138	14,421	4,722	1,472								
2014-15	828	1,46,006	14,920	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038							
2015-16	700	1,38,767	3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220						
2016-17	916	2,06,120	1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8711	4,003	2,086					
2017-18	955	2,12,265		620	15,184	12,445	81,242	54,817	30038	10,736	2,349	242				
2018-19	963	2,49,680			569	6,862	11,000	1,06,700	64895	22,497	15,157	4,507	101			
2019-20	827	2,95,582					4,049	14,526	119,394	75,715	39,833	15,079	2,584	194		
2020-21	594	1,16,785						2,491	3709	51,017	40,161	13,014	5,561	832		
2021-22	791	1,96,580							3,610	10,566	89,694	62,164	24,475	4,030	1,646	396
2022-23	982	3,51,351							1,127	2,150	16,663	1,23,095	1,26,505	62,656	16,288	2,865
2023-24	1,500	5,47,734								2,235	6,783	39,513	2,42,943	1,52,420	66,604	37,235
2024-25	1,584	4,97,235									1,476	3,073	13,415	1,94,791	1,82,895	1,01,586
कुल योग&			**270,020**	**2,05,112**	**1,90,580**	**1,72,048**	**1,61,782**	**2,08,319**	**2,33,745**	**1,79,139**	**2,14,202**	**2,60,688**	**4,15,583**	**4,14,923**	**2,67,432**	**1,42,082**
प्रतिशत परिवर्तन				**-24.0**	**-7.1**	**-9.7**	**-6.0**	**28.8**	**12.2**	**-23.4**	**19.6**	**21.7**	**59.4**	**-0.2**	**#**	

*: रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2013-14 से 2024-25

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत शेयर	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत शेयर	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	214	76	34	21	1	**346**
	प्रतिशत शेयर	8.6	20.9	26.0	38.5	5.9	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	287	180	29	40	5	**541**
	प्रतिशत शेयर	5.8	23.3	11.9	41.7	17.4	**100 (1,79,239)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	263	149	28	42	3	**485**
	प्रतिशत शेयर	5.2	21.0	10.8	43.8	19.1	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	220	110	39	36	4	**409**
	प्रतिशत शेयर	4.8	17.0	17.0	39.6	21.6	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	150	84	45	36	5	**320**
	प्रतिशत शेयर	3.3	11.9	18.6	37.4	28.8	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	128	52	15	24	1	**220**
	प्रतिशत शेयर	5.5	16.8	14.2	53.5	10.0	**100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या	201	125	37	36	2	**401**
	प्रतिशत शेयर	5.6	19.7	20.0	46.9	7.9	**100 (1,42,111)**
2022-23	परियोजनाओं की संख्या	267	158	50	64	8	**547**
	प्रतिशत शेयर	3.9	13.8	13.9	41.3	27.1	**100 (2,66,621)**
2023-24	परियोजनाओं की संख्या	484	265	107	77	11	**944**
	प्रतिशत शेयर	4.6	16.6	20.0	37.1	21.7	**100 (3,91,003)**
2024-25	परियोजनाओं की संख्या	502	234	86	75	10	**907**
	प्रतिशत शेयर	5.2	14.8	17.1	37.2	25.8	**100 (3,67,973)**

टिप्पणी: i . कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में) दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सेदारी है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का कुल योग 100 नहीं हो सकता है।

सारणी ए6: 2013-14 से 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण

अवधि	संख्या और परियोजनाओं का हिस्सा	नया	विस्तार & आधुनिकीकरण	विविधता	अन्य	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत शेयर	65.2	20.1	-	14.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत शेयर	39.4	14.7	0.2	45.7	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	260	64	3	19	**346**
	प्रतिशत शेयर	73.6	14.3	0.1	12.0	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	429	97	4	11	**541**
	प्रतिशत शेयर	78.6	9.9	0.1	11.3	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	396	80	2	7	**485**
	प्रतिशत शेयर	89.0	9.5	0.1	1.5	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	309	80	-	20	**409**
	प्रतिशत शेयर	76.8	19.3	-	3.9	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	262	37	1	20	**320**
	प्रतिशत शेयर	79.8	13.7	-	6.4	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	181	38	1	-	**220**
	प्रतिशत शेयर	94.1	5.9	-	-	**100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या	312	88	1	-	**401**
	प्रतिशत शेयर	89.1	10.8	0.1	0.0	**100 (1,42,111)**
2022-23	परियोजनाओं की संख्या	440	101	-	6	**547**
	प्रतिशत शेयर	93.1	6.1	-	0.8	**100 (2,66,621)**
2023-24	परियोजनाओं की संख्या	767	167	4	6	**944**
	प्रतिशत शेयर	89.1	8.7	0.1	2.2	**100 (3,91,003)**
2024-25	परियोजनाओं की संख्या	734	162	5	6	**907**
	प्रतिशत शेयर	91.6	7.8	0.1	0.5	**100 (3,67,973)**

टिप्पणी: i . कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में) दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

iii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2013-14 से 2024-25

Industry	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
आधारभूत संरचना	87	39.7	74	48.9	108	72.0	204	62.5	150	51.7	122	60.3	99	61.5	63	74.3	95	56.3	135	60.0	245	55.5	207	50.6
i) पावर	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3	58	29.0	53	20.3	139	24.4	146	39.7
ii) दूरसंचार	1	-	1	4.9	1	0.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6	-	-
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1	2	5.9	2	0.4	9	4.8	3	0.6
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2	2	0.2	3	0.8	4	0.0	8	0.2
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2	3	1.1	8	1.9	10	0.5	8	1.2
vi) सड़कें और पुल	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5	30	20.2	69	36.5	82	25.2	42	8.9
धातु और धातु उत्पाद	44	17.4	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8	27	4.3	60	14.6	71	9.3	68	4.6
निर्माण	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8	22	7.4	35	4.0	56	8.0	57	5.6
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	9	2.0	7	0.2	2	0.2	9	0.2	6	0.2	1	0.1	4	-	1	0.1	5	4.0	9	1.1	15	4.4	28	4.6
खाद्य उत्पाद	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5	25	1.7	40	2.5	107	3.0	86	2.6
रसायन और कीटनाशक	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6	20	3.4	16	2.3	33	2.9	24	7.9
वस्त्र	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8	56	4.5	42	2.8	58	2.2	38	1.2
परिवहन सेवाएं	14	0.5	5	0.6	10	1.2	12	0.4	16	4.1	5	0.2	14	1.4	1	0.1	19	2.5	21	0.6	35	2.1	46	2.1
कोक और पेट्रोलियम उत्पाद	1	0.5	1	3.4	2	2.0	2	0.5	1	0.4	-	-	3	8.0	-	-	7	1.0	17	1.1	28	1.6	23	1.8
सीमेंट	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3	3	3.3	2	0.8	11	1.3	4	1.0
परिवहन उपकरण और पुर्जे	14	1.0	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.8	5	0.4	2	0.3	5	0.4	16	0.6	12	1.2	16	1.8
खनन और उत्खनन	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	7	1.8	11	1.2	9	2.2
होटल और रेस्तरां	22	2.2	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	26	1.9	16	1.7	4	2.9	12	0.9	13	0.4	58	1.1	61	1.5
दवाइयों	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5	20	1.3	30	2.1	29	0.8	42	1.0
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	10	0.7	2	0.1	1	-	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3	19	2.3	20	1.1	25	0.7	34	1.5
रबर और प्लास्टिक उत्पाद	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	5	0.5	5	0.3	17	2.1	12	0.8	13	0.8	24	0.7	35	1.9
आईटी सॉफ्टवेयर	3	0.1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	0.7	1	-	-	-	2	0.6	4	1.2	4	0.6	10	3.9
अन्य*	84	11.4	51	3.2	46	4.1	54	2.9	41	2.0	79	13.3	37	9.3	36	7.6	51	5.1	67	2.3	122	3.5	119	4.2
कुल	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**401**	**100**	**547**	**100**	**944**	**100**	**907**	**100**
कुल परियोजना लागत ₹ करोड़ में	**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**1,42,111**		**2,66,621**		**3,91,003**		**3,67,973**	

*: इसमें कागज़ और कागज़ उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का निर्माण, कांच और मिट्टी के बर्तन, चीनी और संबंधित उत्पाद, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, मुद्रण और प्रकाशन, अन्य विनिर्माण और अन्य सेवाएँ जैसे उद्योग शामिल हैं।

टिप्पणी: i . प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण: 2013-14 से 2024-25

राज्य	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
गुजरात	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1	82	11.7	82	14.0	154	14.7	152	21.4
महाराष्ट्र	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5	44	9.6	48	7.9	93	11.7	111	15.1
कर्नाटक	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1	24	6.9	37	7.3	61	11.1	60	6.2
आंध्र प्रदेश	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0	11	2.1	27	4.4	51	10.1	28	9.3
उतार प्रदेश।	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.4	30	13.7	33	12.7	45	16.2	69	7.6	78	7.1
ओडिशा	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.4	6	1.9	2	0.1	9	2.2	12	11.8	23	6.7	18	4.6
तेलंगाना	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9	16	3.4	30	1.9	40	4.1	42	2.8
राजस्थान	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1	32	12.6	22	3.1	61	3.6	45	7.3
झारखंड	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	0.0	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2	6	0.8	12	1.9	17	3.4	7	1.3
मध्य प्रदेश	30	6.1	14	3.9	21	7.0	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8	18	4.2	35	5.0	56	3.4	41	2.7
छत्तीसगढ	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2	4	0.8	8	1.4	26	3.3	24	1.1
तमिलनाडु	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7	40	8.8	44	4.7	83	3.0	73	4.7
बिहार	6	0.2	4	0.1	6	0.2	4	0.2	3	0.1	6	0.4	6	3.4	1	0.0	5	3.4	6	1.6	13	2.6	11	0.9
पश्चिम बंगाल	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4	11	2.6	16	1.0	28	2.3	34	2.3
जम्मू और कश्मीर	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	11	0.4	3	0.3	5	0.2	5	0.2	23	3.1	36	1.9	54	3.8
पंजाब	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7	15	2.2	21	2.5	34	1.6	28	1.5
हरयाणा	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8	14	2.0	14	1.0	25	1.5	20	0.6
दिल्ली	5	0.4	2	0.1	1	0.1	5	0.3	6	1.2	8	1.3	3	0.5	2	0.1	3	0.6	12	0.4	10	1.2	14	0.3
असम	4	0.3	2	0.2	4	0.4	10	0.6	5	0.8	4	0.2	1	0.3	3	4.4	2	0.0	6	0.7	13	0.9	14	1.2
हिमाचल प्रदेश	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2	7	1.2	11	2.2	10	0.3	9	0.1
केरल	3	0.0	4	0.2	4	0.1	6	2.7	3	0.1	6	0.9	3	1.0	-	-	5	4.2	12	0.9	11	0.2	12	0.3
गोवा	-	-	-	-	1	0.0	3	0.6	2	1.9	3	1.8	2	0.1	-	-	3	3.0	3	0.8	4	0.1	3	0.6
उत्तराखंड	5	0.1	5	0.2	2	0.1	11	0.4	6	0.4	9	0.4	5	0.1	2	0.1	2	0.4	5	0.1	8	0.1	14	0.3
बहु-राज्य #	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4	7	4.0	10	5.5	12	4.4	9	4.5
अन्य*	4	0.2	3	0.9	5	1.1	4	0.3	7	2.4	5	1.7	1	0.0	2	0.3	3	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.1
कुल	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**401**	**100**	**547**	**100**	**944**	**100**	**907**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**142,111**		**2,66,621**		**3,91,003**		**3,67,973**	

#: इसमें कई राज्यों की परियोजनाएँ शामिल हैं।

*: इसमें शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

टिप्पणी: i . प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।